बॉन्ड बाजार को जी-सैप पर घोषणा का इंतजार

अनूप रॉय
मुंबई, 3 जून

- दूसरी तिमाही के लिए न्यूनतम 1 लाख करोड़ रुपये के जी-सैप का अनुमान है
- केंद्रीय बैंक करीब 60,000 करोड़ रुपये के बॉन्डों की खरीदारी पहले ही कर चुका है
- लेकिन प्रतिफल नरम बनाए रखने के लिए इसे बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये भी किया जा सकता है

बॉन्ड बाजार इस बारे में आरबीआई की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अपने सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम (जी-सैप) के तहत केंद्रीय बैंक ने दूसरी तिमाही में खरीदारी की क्या योजना बनाई है, और क्या जी-सैप के दूसरे चरण से कोई शर्त जुड़ी होगी।

केंद्रीय बैंक ने पहली तिमाही में जी-सैप के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदने की योजना बनाई है, जिसमें वह 60,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड की खरीदारी पहले ही कर चुका है।

शुक्रवार की मौद्रिक नीति इस तिमाही के लिए आखिरी बैठक होगी और इसलिए नीतिगत समीक्षा में दूसरी तिमाही के आंकड़े स्पष्ट किए जा सकते हैं।

बॉन्ड डीलरों का कहना है कि भले ही, जी-सैप की घोषण पहली तिमाही के अंत में की जा सकती हो, लेकिन बॉन्ड प्रतिफल में तेजी के संकेत दिखने और केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिफल नियंत्रित करने के कदम उठाने से नीतिगत मंच बॉन्ड बाजार की चिंताएं दूर करने का अच्छा अवसर होगा।

बाजार में यह धारणा है कि दूसरी तिमाही के लिए जी-सैप कम से कम 1 लाख करोड़ का होगा, लेकिन इसे बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये भी किया जा सकता है। घरेलू बाजार के प्रमुख आनंद बागड़ी के अनुसार, जी-सैप सभी तिमाहियों में समान रूप से प्रति एक लाख करोड़ रुपये तक वितरित हो सकता है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस के उपाध्यक्ष (निवेश) राम कमल सामंता का मानना है कि जी-सैप राशि आगामी तिमाहियों में बढ़ सकती है। उन्हें उम्मीद है कि अगली तिमाही के लिए जी-सैप बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

एयू एसएफबी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष देबेंद्र दास ने कहा, 'जी-सैप 1 लाख करोड़ रुपये और 1.5 लाख करोड़ रुपये के बीच रहने की संभावना है।'

दास ने कहा, 'यदि जी-सैप के बारे में घोषणा नहीं की जाती है तो 10-वर्षीय प्रतिफल 25 आधार अंक तक बढ़ जाएगा।'

हालांकि एक बड़े घरेलू बैंक से जुड़े वरिष्ठ बॉन्ड डीलर ने कहा कि यदि आरबीआई शुक्रवार को 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के जी-सैप की घोषणा नहीं करती है तो प्रतिफल बढ़ जाएगा।

हालांकि सभी इसे लेकर सहमत नहीं हैं। एचडीएफसी लाइफ में निर्धारित आय के प्रमुख बद्रीश कुल्हाली ने कहा, 'वास्तव में, जी-सैप 1.0 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि आरबीआई के लिए एक बड़ी छलांग थी। अप्रैल की नीति तक राशि को लेकर किसी तरह की प्रतिबद्धता से परहेज किया गया था। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई ऊंचे आंकड़ों की प्रतिबद्धता के साथ ज्यादा सक्रियता दिखाएगा।'

जी-सैप को लेकर उम्मीदों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 6 प्रतिशत के पार पहुंचना शुरू हो गया है, जिसे आरबीआई नियंत्रित करना चाहेगा।

बाजार में मजबूत संकेत भेजने के लिए आरबीआई ने बॉन्ड नीलामियों पर ध्यान केंद्रित किया था। प्राथमिक डीलरों को 10,735.67 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदने थे, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड वर्ष 2026 की परिपक्वता से जुड़े हुए थे।

दीर्घावधि बढ़त परिदृश्य को लेकर पीवीआर पर तेजी का नजरिया

निकिता वशिष्ठ
नई दिल्ली, 3 जून

मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री पर कोविड-19 महामारी का भारी असर पड़ा है क्योंकि आम लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया और मनोरंजन पूरी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी सिनेमा कंपनी को हालांकि देसी व विदेशी विदेशकों से मजबूत समर्थन मिला है। कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न पर नजर डालने से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक सितंबर तिमाही (2020-21) कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे, जब महामारी से संबंधित पाबंदियां भारत में नरम हो रही थीं। दूसरी तिमाही के आखिर की 34.6 फीसदी हिस्सेदारी को एफआईआई ने वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही में बढ़ाकर 42.6 फीसदी पर पहुंचा दिया। सालाना आधार पर भी वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही के आखिर में रही 38.55 फीसदी हिस्सेदारी के मुकाबले भी हिस्सेदारी बढ़ी है।

ऐसे में यह भरोसा क्या बताता है? विश्लेषकों का मानना है कि एफआईआई अल्पावधि की परेशानी से आगे देख रहे हैं और पीवीआर की दीर्घावधि की बढ़त को लेकर आश्वस्त हैं।

प्रभुदास लीलाधर के शोध विश्लेषक जिनेश जोशी ने कहा, अहम मल्टीप्लेक्स कंपनियों की ढांचागत बढ़त की कहानी मजबूत बनी हुई है और जब कोविड महामारी खत्म होगी तो ये कंपनियां पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती के साथ उभरेंगी। सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते रकम जुटाना आसान होगा।

हाल में कंपनी ने गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र के जरिये 500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना की घोषणा की है। इससे पहले वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही में कंपनी ने क्यूआईपी के जरिये 800 करोड़ रुपये जुटाए थे। सिंगल स्क्रीन कंपनियों के मुकाबले यह बिल्कुल उलट है, जो संघर्ष कर रही हैं।

कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज के शोध विश्लेषक जयकुमार दोशी ने कहा, आने वाले समय में सिंगल स्क्रीन बंद होने की रफ्तार बढ़ सकती है और अन्य सिनेमा ऑपरेटरों के मुकाबले पीवीआर मजबूती से उभर सकती है। साथ ही दूसरी लहर के खात्मे, टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने और सिनेमा का परिचालन बहाल होने के साथ वह बढ़ी मांग को पूंजीकृत करने के लिहाज से भी बेहतर स्थिति में रह सकती है।

एमके ग्लोबल के शोध विश्लेषकों नवल सेठ और सोनाली शाह ने कहा, नए फंड के अलावा लागत नियंत्रण, किराए में छूट और वितरकों के साथ राजस्व साझेदारी करार उसका अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए अहम होगा।

हालांकि अल्पावधि के अवरोध को देखते हुए ज्यादातर विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 22 व वित्त वर्ष 23 के लिए आय अनुमान में कटौती की है और इसमें इस वित्त वर्ष के न्यूनतम राजस्व को समाहित किया है।

उदाहरण के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एमके ग्लोबल ने वित्त वर्ष 22 व वित्त वर्ष 23 के लिए एबिटा अनुमान भारी कटौती की है। प्रभुदास लीलाधर ने ने वित्त वर्ष 22 का एबिटा अनुमान 43 फीसदी घटाया है जबकि वित्त वर्ष 23 का अनुमान बरकरार रखा है। पीवीआर का शेयर सुदृढ़ रहा है और इस साल अब तक के आधार पर 0.3 फीसदी ऊपर है। इसकी तुलना में बेंचमार्क एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स बुधवार तक 8.5 फीसदी चढ़ा है।

विदेशी बॉन्ड से टाटा मोटर्स ने जुटाए 42.5 करोड़ डॉलर

भारतीय वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने असुरक्षित विदेशी बॉन्ड के जरिए 4.35 फीसदी की दर पर 42.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं, जिसका इस्तेमाल पुराने कर्ज को समाप्त करने और खर्च पूरा करने में किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में कंपनी ने रकम जुटाने की पुष्टि की है और कहा है कि वह 31.8 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल मौजूदा कर्ज को समाप्त करने में करेगी जबकि बाकी रकम का इस्तेमाल कंपनी के सामान्य कामकाज पर होगा।

यह बॉन्ड जून 2026 में परिपक्व होगा। ब्रिटिश ब्रांड जगुआर लैंड रोवर के मालिकाना हक वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने कहा कि उसे एशिया व यूरोप में निवेशकों की खासी दिलचस्पी देखने को मिली है और इस बॉन्ड को पांच गुना से ज्यादा बोली मिली। इस बॉन्ड को स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स रेटिंग्स सर्विस ने बी रेटिंग दी है। भारत में एएए रेटिंग वाली सरकारी फर्म को मौजूदा स्तर पर 5 साल के लिए रकम जुटाने पर करीब 5.9 फीसदी चुकाना पड़ेगा, ऐसे में मुद्रा परिवर्तन की लागत के बावजूद विदेश से रकम जुटाना आकर्षक है।

विदेश में बिक्री बॉन्ड जारी करने वालों को ज्यादा रकम जुटाने में सक्षम बनाता है और अपने डेट इन्वेस्टर का आधार विशाखित करने में भी मदद मिलती है। करीब दो दर्जन भारतीय कंपनियों ने संयुक्त रूप से साल 2020 में विदेश में 14.01 अरब डॉलर जुटाए, जो एक साल पहले के 26.5 अरब डॉलर के मुकाबले कम है। यह जानकारी ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म डीलॉजिक के आंकड़ों से मिली। टाटा मोटर्स के ऊपर पिछले वित्त वर्ष के आखिर में 409 अरब रुपये का कर्ज था। कंपनी ने साल 2020 में कहा था कि उसकी योजना तीन साल में कर्ज मुक्त होने की है। *रॉयटर्स*

एमएफ के लिए बढ़ाई गई विदेशी निवेश की सीमा

चिराग मडिया
मुंबई, 3 जून

बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को म्युचुअल फंडों के लिए विदेशी निवेश की सीमा में संशोधर कर दिया। नियामक के परिपत्र में कहा गया है, म्युचुअल फंड प्रति म्युचुअल फंड अधिकतम 1 अरब डॉलर का विदेशी निवेश कर सकते हैं, जो उद्योग की कुल सीमा 7 अरब डॉलर की सीमा में होगा।

म्युचुअल फंडों ने बाजार नियामक सेबी से निवेश की सीमा बढ़ाने की मांग की थी। पिछले साल नवंबर में सेबी ने विदेशी निवेश की सीमा प्रति म्युचुअल फंड 30 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 60 करोड़ डॉलर कर दिया था।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि इस घोषणा की काफी जरूरत थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई म्युचुअल फंड योजनाएं काफी ज्यादा निवेश हासिल कर रही थी। सेबी ने अपने परिपत्र में कहा है, म्युचुअल फंड विदेशी ईटीएफ में प्रति म्युचुअल फंड अधिकतम 30 करोड़ डॉलर का निवेश कर सकते हैं और यह अमेरिका में उद्योग की कुल सीमा 1 अरब डॉलर के भीतर होगी। पहले यह सीमा 20 करोड़ डॉलर प्रति म्युचुअल फंड थी।

भारतीय फंड हाउस पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करने वाले फंड ऑफ फंड्स पेश कर चुके हैं। ये योजनाएं निवेशकों को वैश्विक इक्विटी में विशाखन की पेशकश करती हैं।

सॉफ्टबैंक समर्थित ओला ने नेतृत्व टीम का विस्तार किया

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 3 जून

सॉफ्टबैंक-समर्थित मोबिलिटी कंपनी ओला ने दो मुख्य वित्तीय अधिकारियों की नियुक्ति के साथ अपनी नेतृत्व टीम का विस्तार किया है। जी आर अरुण कुमार को ओला के समूह सीएफओ और ओला इलेक्ट्रिक के सीएफओ के तौर पर नियुक्त किया गया है जबकि स्वयं सौरभ को ओला के मोबिलिटी, वित्तीय सेवा और फूड व्यवसायों के लिए सीएफओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ओला के चेयरमैन एवं समूह सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा, 'ओला हमें हम विश्वस्तरीय नेतृत्व टीम तैयार कर रहे हैं और दुनियाभर से श्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियुक्त कर रहे हैं। अरुण कुमार और स्वयं सौरभ बड़े और वैश्विक संगठनों तथा निर्माण, एफएमसीजी समेत विभिन्न उद्योगों की गहन वित्तीय दक्षता से संपन्न हैं।'

स्वत: बहाल नहीं हो सकते जेट एयरवेज के स्लॉट

सुब्रत पांडा
मुंबई, 3 जून

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एनसीएलटी में जमा कराए अपने अतिरिक्त शपथपत्र में स्लॉट को लेकर अपने रुख को दोहराया है। मंत्रालय ने कहा है कि समाधान आवेदक पुराने स्लॉट का दावा नहीं कर सकता, जो उसे पहले से आवंटित थे।

मंत्रालय और डीजीसीएस ने अपने शपथपत्र में कहा है, जेट एयरवेज को दिए गए स्लॉट को स्वत: बहाल नहीं किया जा सकता और जेट एयरवेज के स्लॉट का आवंटन नियमों व दिशानिर्देशों के मुताबिक होगा। जब जेट एयरवेज ने परिचालन बंद किया था तब वे स्लॉट अस्थायी आधार पर विभिन्न विमानन कंपनियों को वितरित कर दिए गए थे। साथ ही जिन विमानन कंपनियों को इन स्लॉटों के इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था उन्हें तत्काल ढांचा बनाने को कहा गया था और उन्होंने इस पर मोटा निवेश भी किया था ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। शपथपत्र में कहा गया है, इस लिहाज से आवंटन हालांकि विमानन कंपनियों को अस्थायी तौर पर किया गया था, लेकिन बिना किसी उचित आधार के उनसे ये स्लॉट वापस नहीं लिए जा सकते।

> नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एनसीएलटी में जमा कराए शपथपत्र में ये बातें कही हैं

इसमें कहा गया है, जब जेट एयरवेज स्लॉट के लिए आवेदन करेगी तब सभी विमानन कंपनियों के बीच बिना किसी पक्षपात के इनका आवंटन किया जाएगा और ये आवंटन स्लॉट आवंटन से संबंधित दिशानिर्देश 2013 के मुताबिक होंगे। इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। अपने शपथपत्र में कालरॉक-जालान कंसोर्टियम (जो जेट एयरवेज के कामयाब समाधान आवेदक हैं) ने कहा है, उन्हें लगा था कि जेट के स्लॉट व ट्रैफिक राइट्स उन्हें वापस मिल जाएंगे। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल और आवेदक ने लगातार विमानन मंत्रालय व डीजीसीए को पत्र लिखकर सभी स्लॉटों व ट्रैफिक राइट्स पर दावा किया था।

कंपनियों ने बढ़ाए इस्पात के दाम

प्रमुख घरेलू इस्पात विनिर्माताओं ने हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) और कोल्ड रोल्ड कॉइल (सीआरसी) के दाम क्रमश: 4,000 रुपये और 4,900 रुपये प्रति टन तक बढ़ा दिए हैं। उद्योग सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस मूल्य वृद्धि के बाद, एक टन एचआरसी की कीमत 70,000-71,000 रुपये होगी, जबकि खरीदारों को सीआरसी 83,000-84,000 रुपये प्रति टन के दाम पर मिलेगी। एचआरसी और सीआरसी इस्पात की चादरें होतीं है जिनका उपयोग ऑटो, उपकरणों और निर्माण क्षेत्र जैसे उद्योगों में किया जाता है। इसलिए, इस तरह के इस्पात की कीमतों में कोई भी वृद्धि, वाहनों, उपभोक्ता वस्तुओं और निर्माण की लागत को भी प्रभावित करती है। इन क्षेत्रों के लिए यह कच्चा माल का काम करता है।

सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल और एएमएनएस इंडिया देश की प्रमुख इस्पात कंपनियां हैं। ये कंपनियां संयुक्त रूप से भारत के कुल इस्पात उत्पादन में लगभग 55 फीसदी का योगदान करती हैं।

ग्रे बाजार में चढ़ा पेटीएम का शेयर

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 3 जून

डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम का शेयर ग्रे बाजार में 80 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया। गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में कारोबार करने वाले एक कारोबारी का कहना है कि यह तेजी इस उम्मीद से आई है कि जब इस साल के अंत में कंपनी सूचीबद्ध हो जाएगी तो उसके बाद शेयर कीमत की वैल्यू मौजूदा स्तरों के मुकाबले कम से कम 40 प्रतिशत ज्यादा होगी।

गैर-सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों की खरीदारी और बिक्री को सुगम बनाने वाली फर्म अनलिस्टेड जोन के निदेशक दिनेश गुप्ता ने कहा, 'यह शेयर एक महीने पहले के 12,500 से चढ़कर 22,000 रुपये पर पहुंच गया है। कारोबारी यह उम्मीद कर रहे हैं आईपीओ में शेयर की वैल्यू 35,000 रुपये पर होगी। कंपनी वैल्यू में कमी लाने के लिए बोनस इश्यू भी लाएगी।'

ऐंट ग्रुप समर्थित कंपनी ने आईपीओ के जरिये करीब 22,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपने बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी हासिल की है। यह पहली पेशकश कैलेंडर वर्ष के अंत से पहले बाजार में आने की संभावना है। यदि पेटीएम का आईपीओ बाजार में आता है तो यह देश में सबसे बड़ी पेशकश होगी। रिपोर्टों के अनुसार, पेटीएम अपने आईपीओ में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का मूल्यांकन हासिल होने की संभावना देख रही है।

बाजार कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा ग्रे बाजार भाव से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन का संकेत मिल रहा है।

नवंबर 2019 में कंपनी ने 1.1 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर 1 अरब डॉलर की रकम जुटाई थी। पेटीएम देश में सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान कंपनियों में से एक के तौर पर पहचान बना चुकी है। यूपीआई पेमेंट के संदर्भ में करीब 12 प्रतिशत की बाजार भागीदारी के साथ उसका तीसरा स्थान है। मार्च में, उसने 1.4 अरब से ज्यादा के लेनदेन दर्ज किए, जो फरवरी के 1.2 अरब लेनदेन के मुकाबले ज्यादा हैं। कंपनी ने कहा कि यह वृद्धि ऑफलाइन और वित्तीय सेवाओं की मदद से हासिल हुई थी। कंपनी के अनुसार, वह मासिक आधार पर लगातार 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर रही है।

फिनटेक कंपनी ने बाद में बाजार में अपनी पहुंच और राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी ने हाल में कई नए उत्पाद और सेवाओं को पेश किया है। उसने निवेश उपयोगकर्ताओं के लिए भी सेवाएं पेश की हैं।

कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-2022 में पेटीएम मनी के लिए हर साल 1 करोड़ उपयोगकर्ता और 7.5 करोड़ सालाना लेनदेन दर्ज करना है। पेटीएम मनी उसका शेयर एवं म्युचुअल फंड निवेश प्लेटफॉर्म है। पेटीएम के बारे में बर्न्सटीन द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी पेमेंट व्यवसाय से आगे बढ़कर एक संपूर्ण फिनटेक प्लेटफॉर्म में तब्दील होने के लिए तैयार है।

Nucleus Software Exports Limited

NUCLEUS SOFTWARE

CIN : L74899DL1989PLC034594
Registered Office: 33-35, Thyagraj Nagar Market, New Delhi - 110003
Tel : +91 - 120 - 4031400; Fax : +91 - 120 - 4031672
Email : investorrelations@nucleussoftware.com, Website: www.nucleussoftware.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS OF NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LIMITED FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2021

(Amount in Rupees Lacs)

SL. No.	Particulars	CONSOLIDATED				STANDALONE			
		Quarter Ended		For the year ended		Quarter Ended		For the year ended	
		31 March 2021	31 March 2020	31 March 2021	31 March 2020	31 March 2021	31 March 2020	31 March 2021	31 March 2020
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total income from operations (net)	12,418	13,823	51,353	52,083	11,081	11,894	45,436	44,420
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	3,552	3,811	15,381	11,678	3,449	4,602	14,652	12,905
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	3,552	3,811	15,381	11,678	3,449	4,602	14,652	12,905
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2,735	2,814	11,795	8,899	2,634	3,525	11,204	10,222
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,586	2,172	11,985	8,152	2,557	2,884	11,379	9,373
6.	Equity Share Capital	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904
7.	Reserves as shown in the Audited balance sheet of previous year	-	-	64,298	53,184	-	-	61,790	51,282
8.	Earnings Per Share - (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (Not annualised for quarters)								
	Basic (INR)	9.42	9.69	40.62	30.64	9.07	12.14	38.58	35.20
	Diluted (INR)	9.42	9.69	40.62	30.64	9.07	12.14	38.58	35.20

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.nucleussoftware.com.
2. In view of the pandemic relating to COVID-19, the Group has considered internal and external information and has performed an analysis based on current estimates while assessing the provision towards employee benefits and recoverability of right-of-use assets, trade receivables, investments and other current and financial assets, for any possible impact on the Standalone and Consolidated Financial Results. The Group has also assessed the impact of this whole situation on its capital and financial resources, profitability, liquidity position, internal financial reporting controls etc. and is of the view that based on its present assessment this situation does not materially impact these Standalone and Consolidated financial results. However, the actual impact of COVID-19 on these financial results may differ from that estimated due to unforeseen circumstances and the Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions. The Group had held back annual increments, variable pay at senior levels, confirmations of employees and new recruitments and cut down travelling expenses, marketing events and advertisement costs for the year 2020-21, because of the uncertainty unfolding due to COVID 19. The Group is keeping a close eye on the situation and is reviewing its decisions every quarter as per emerging situation.The Management has taken measures to compensate its employees through a special bonus which it has started distributing to its employees from the quarter ended 31 December 2020.
3. On 30 May 2021 (after the end of the period of 31 March 2021 to which these financial results pertain) the Group experienced an information security incident involving a ransomware attack and consequent isolation of impacted IT services. In response to this, management has ismmediately initiated comprehensive containment and remediation efforts to address the incident. Recovery and restoration of all impacted application and data is underway. The Group has also started the process to investigate and ascertain the nature, extent and causes of data breach. The impact of this cyber security incident including any possible litigations and claims is presently uncertain.

By Order of the Board
For Nucleus Software Exports Limited
Sd/-
VISHNU R DUSAD
Managing Director

Place: Noida
Date : 3 June 2021